राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर पीठ

खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 250/1992

राजस्थान सरकार

----अपीलार्थी

बनाम

1. शिव नारायण पुत्र श्री बलदेवा राम
2. श्यामसुन्दर पुत्र श्री भंवर लाल
3. छगन लाल पुत्र बलदेव राम (समाप्त: 12.09.2022)
4. बलदेव राम पुत्र पंछी राम (समाप्त: 12.09.2022)
5. प्रेम कुमार पुत्र छगन लाल
6. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरलाल
7. जीता राम पुत्र छगन लाल (समाप्त: 12.09.2022)

जाति नाई

सभी अर्जुनसर, थाना क्षेत्र महाजन, जिला बीकानेर के निवासी हैं।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री बी.आर. बिश्नोई, पी.पी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री श्याम एस. खत्री

माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई

माननीय न्यायमूर्ति फरजंद अली

<u>निर्णय</u>

निर्णय सुरक्षित करने की तारीख : 18.10.2022

निर्णय उच्चारित करने की तारीख : 13.12.2022

माननीय फरजंद अली, न्यायमूर्ति

<u>रिपोर्टेबल</u>

यह अपील राज्य द्वारा सीआरपीसी की धारा 378(3) के तहत दायर की गई है। सत्र प्रकरण संख्या 104/1988 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 11.12.1989 के बरी करने के निर्णय के खिलाफ, जिसके तहत आरोपी-प्रत्यर्थीगण को आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147, 148 और 302 के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया गया था।

अपील के दौरान, सात अपीलार्थीगण में से तीन, अर्थात् अपीलार्थी संख्या 3 छगन लाल पुत्र बलदेव राम, अपीलार्थी संख्या 4 बलदेव राम पुत्र पंछी राम और अपीलार्थी संख्या 7 जीता राम पुत्र छगन लाल, का निधन हो गया है और इस प्रकार, अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2022 के आदेश के माध्यम से उनकी सीमा तक समाप्त कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट दिनांक 21.08.2022 के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 1-शिव नारायण पुत्र बलदेवा राम, अपीलार्थी संख्या 2- श्याम सुंदर पुत्र श्री भंवर लाल, अपीलार्थी संख्या 5-प्रेम कुमार पुत्र छगन लाल और अपीलार्थी संख्या 6-अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जीवित हैं और वर्तमान में अर्जुनसर, पुलिस थाना महाजन, जिला बीकानेर में रहते हैं। इस प्रकार, अब अपील की सुनवाई अपीलार्थी संख्या 1-शिव नारायण पुत्र बलदेव राम, अपीलार्थी संख्या 2-श्याम सुंदर पुत्र श्री भंवर लाल, अपीलार्थी संख्या 5-प्रेम कुमार पुत्र छगन लाल एवं अपीलार्थी क्रमांक 6- अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरलाल। तक की जा रही है।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रथम सूचक बृजलाल ने दिनांक 23.10.1988 को पुलिस थाना महाजन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने भाई चानन राम के साथ जीप में गंगानगर से सहजरासर जा रहा था और वे जीप में पानी डालने के लिए रुके थे। अर्जुनसर बस स्टैंड के पास पानी क्योंकि उनकी जीप ज़्यादा गरम हो रही थी। वह गाड़ी में पानी डालने लगा, जबकि उसका भाई चानन राम अपने रिश्तेदार सत्यनारायण के यहां गया, जहां दीवार खड़ी की जा रही थी। जब उसने लोगों का शोर सुना तो वह सत्यनारायण के बाड़े की ओर गया, जहां लीलाधर और राधाकिसन भी मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके भाई चानन राम को सात आरोपियों ने घेर लिया और उसकी (चानन (चानन राम) बंदूक आरोपी शिव नारायण ने छीन ली. वे उसे बाड़े के अंदर ले गए और शिव शिव नारायण ने अपने पास मौजूद बंदूक की बट से उस पर वार कर दिया। आरोपी बलदेवा

बलदेवा राम ने कहा कि झगड़े का मूल कारण चानन राम है और उसने दूसरों को उसे खत्म करने के लिए उकसाया और उसी समय, आरोपी श्याम सुंदर एक कुदाल लाया, आरोपी शिव नारायण एक फावड़ा लाया, आरोपी छगन लाल एक काले टायर की रस्सी लाया लाया और आरोपी अशोक लाठी लेकर आया। इसके बाद बलदेव राम को छोड़कर सभी आरोपियों ने चानन राम को पकड़ लिया और बांध दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब आरोपी छगन लाल, प्रेम कुमार और जीता राम चानन राम को पकड़े हुए थे, तो आरोपी श्याम सुंदर, शिव नारायण और अशोक उसके साथ मारपीट कर रहे थे और आरोपी बलदेव राम बाहर से उन्हें यह कहकर प्रोत्साहित कर रहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. जिंदा छोड़ दिया जाए और उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाए. इस हंगामे के कारण और भी लोग यह देखने के लिए वहां एकत्र हो गए कि क्या हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा कहा गया है कि आरोपी घटना स्थल से अपने हथियार लेकर चले गये तथा चानन राम की बन्दूक बाड़े में ही छोड़ गये तथा जब लीलाधर एवं राधाकिशन ने साल (लाउंज) में जाकर चानन राम को देखा तो उसका गला घोंट दिया। काट दिया गया था, वह खून से लथपथ था और चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया था।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस स्टेशन, महाजन में आईपीसी की धारा 147, 148, 302 और 149 के तहत एफआईआर संख्या 55/1988 दर्ज की गई। अपनी सामान्य जांच के हिस्से के रूप में, पुलिस ने अपराध स्थल का निरीक्षण किया, गवाहों की गवाही दर्ज दर्ज की, आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, हथियारों की बरामदगी की गई। पुलिस ने उस स्थान के स्वामित्व के संबंध में भी जांच की जहां कथित घटना हुई थी। जांच के समापन के बाद, पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149, 341, 342, 114/149 के तहत अपराध के लिए लिए चालान प्रस्तुत किया गया। चूँकि, आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मामला 07.12.1988 को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर को सौंपा गया और मुकदमा शुरू किया गया। विद्वान निचली अदालत द्वारा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148 और 302 r/w 149 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए गए थे, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध

अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का अनुरोध किया।

मुकदमे में जांच के दौरान 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन पक्ष द्वारा 44 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जब आरोपियों से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया और अपने बचाव में चार दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आरोपी बलदेव राम ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि जिस बाड़ा में कथित घटना हुई थी वह उसकी पत्नी मथुरा के नाम पर था; जिस भूखंड पर बाड़ा बनाया गया वह भी मथुरा का था; बाड़ा में लगाए गए बिजली और पानी के कनेक्शन भी उसके नाम पर जारी किए गए थे और सरपंच मनीराम ने प्रदर्श डी-4 के अनुसार इस तथ्य को प्रमाणित किया था। इसमें आगे कहा गया है कि उन्होंने चानन राम और सत्यनारायण के खिलाफ आईपीसी की धारा 107 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन वे सरपंच मनीराम के साथ मिले हुए थे और इस प्रकार, अपीलीय परिणाम के बावजूद सत्यनारायण के पक्ष में एक मनगढ़ंत पट्टा बनाया गया था। जिस साजिश पर कथित अपराध हुआ था, उसके संबंध में लंबित कार्यवाही बलदेव राम और मथुरा के पक्ष में दी गई थी। उन्होंने अपने 313 सीआरपीसी बयान में आगे कहा कि चानन राम का व्यवहार एक उपद्रवी गुंडे जैसा था और वह गरीब लोगों से जमीनें छीन लेता था। चानन राम पर कई मामले लंबित हैं. घटना के तीनों कथित चश्मदीद गवाह लीलाधर, राधाकिशन और बृजलाल मृतक चानन राम के करीबी रिश्तेदार हैं।

धारा 313 के तहत आरोपी जीता राम के बयान से पता चलता है कि अशोक भंवर सिंह (मिस्त्री/राजमिस्त्री) और मजदूर शेराराम के साथ चिनाई के काम के लिए अपनी दादी के के घर गया था। जब वे काम कर रहे थे, बृजलाल और चानन राम आये थे; जब बृजलाल सत्यनारायण के घर गया, तो चानन राम उनके पास आया और उन्हें प्लॉट छोड़ने की धमकी दी। उसने मजदूरों से कहा कि काम बंद करो और चले जाओ, नहीं तो वह उन्हें मार मार डालेगा। दोनों कर्मचारी मौके से भाग गए। फिर, चानन राम ने अपनी बंदूक निकाली और दोनों आरोपियों, जीता राम और अशोक के पास आते हुए उसमें कारतूस डालने लगा। जीता राम और अशोक डर के मारे कमरे की ओर भागे और खुद को बचाने के लिए लकड़ी का डंडा और फावड़ा उठा लिया। जब चानन राम, जो उनका पीछा कर रहा था, कमरे में

दाखिल हुआ, तो उन्होंने अपने-अपने औजारों से उस पर हमला कर दिया। जीता राम ने आगे कहा है कि उसने चानन राम को चोटें पहुंचाईं और परिणामस्वरूप, वह जमीन पर गिर गिर गया; गिरने के कारण उसके हाथ में जो बंदूक और कारतूस था, वह भी जमीन पर गिर गिर गया और उसी समय, जीता राम ने बंदूक और कारतूस को उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे चानन राम उठकर उन पर हमला नहीं कर सका। जब वे दोनों जा रहे थे, तो उसने कोठे के बाहर चानन राम के जूते देखे और बताया कि जब चानन राम उन्हें मारने के लिए दौड़ा था, तो तीन चश्मदीद गवाहों, लीलाधर, बृजलाल और राधाकिशन में से कोई भी आसपास नहीं था। दरअसल, उनका कहना है कि उनके और अशोक के अलावा बाकी आरोपी आरोपी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। जीता राम के बयान के अनुसार रस्सी कोठे में पड़ी हुई थी और दोनों आरोपियों ने चानन राम को न तो बांधा था और न ही रोका था। इसके बाद उसने जाकर महाजन थानेदार को घटना के बारे में बताया। पुलिस अधिकारी ने निजी जीप में महाजन अस्पताल के डॉक्टर और जीता राम को साथ लिया और घटना स्थल पर पहुंचे. डॉक्टर ने बताया कि चानन राम की मौत हो गयी है और तब तक वहां काफी लोग जमा हो गये थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चूंकि अब उसकी मौत हो चुकी है, है, इसलिए किसी को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उसका भाई भी ऐसा ही करेगा। अगले 10-15 मिनट में बृजलाल घटनास्थल पर पहुंचे और वह अधिकारी के साथ थाने चले गये। करीब डेढ़ घंटे बाद वे वापस आये और जीता राम व अशोक को तब तक वहीं रुकने को कहा गया। घटना स्थल पर पुलिस पदाधिकारी के वापस आते ही उन्हें थाने ले जाया गया। अंत में, जीता राम ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और उनके खिलाफ झूठा मामला थोपा गया है।

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अशोक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण जीता राम द्वारा अपने बयान में बताए गए घटना के विवरण से मेल खाता है।

इसके बाद, अभियुक्तों और सरकारी अभियोजक के अधिवक्ता को सुनने और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए गवाहों की गवाही और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की विस्तार से जांच करने के बाद, विद्वान निचली अदालतने सभी अभियुक्तों को अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आक्षेपित निर्णय से बरी कर दिया। उचित संदेह से परे प्रमाणित

नहीं पाया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, राज्य द्वारा सीआरपीसी की धारा 378(3) तहत वर्तमान अपील की अनुमति दी गई थी।

अपील की विशेष अनुमति के आवेदन को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और इसे अपील के ज्ञापन के रूप में मानने का निर्देश दिया गया था और दिनांक 06.07.1992 के आदेश द्वारा आरोपी-प्रत्यर्थीगण को जमानती वारंट जारी किए गए थे।

श्री बी.आर. अपीलार्थी-राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता बिश्नोई का कहना है कि निचली अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा उसके सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की सराहना करने में विफल रही है और मामले के तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं पर सही ढंग ढंग से विचार नहीं किया है। निचली अदालतद्वारा दिया गया बरी करने का निर्णय गलत है क्योंकि तीन चश्मदीद गवाहों की गवाही पर गलत तरीके से इस कारण से अविश्वास किया गया है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी और वे इच्छुक गवाह थे। उनका कहना है कि निचली अदालतद्वारा यह गलत माना गया कि एफआईआर (प्रदर्श पी-31) एक जांच के का दस्तावेज था, बल्कि इसे गवाह बृज लाल ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज कराया था और यह मृतक चानन राम था। हमलावर कौन था। दो अभियुक्तों, जीता राम और अशोक द्वारा उठाई गई निजी बचाव के अधिकार की दलील को निचली अदालतने बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार कर लिया। आरोपी श्याम सुंदर, अशोक और शिव नारायण की निशानदेही निशानदेही पर की गई बरामदगी अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा सिद्ध की गई है। डॉक्टर की गवाही के अनुसार, चानन राम के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक चानन राम के हाथ और पैर बंधे नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह संयोग की बात है कि संयुक्ताक्षर के निशान दिखाई देंगे या नहीं क्योंकि आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई रस्सी टायर से बनी थी और अन्य रस्सियों की तुलना में नरम थी। आक्षेपित निर्णय में यह गलत तरीके से देखा गया कि आरोपी श्याम सुंदर की कोई संलिप्तता नहीं थी जबकि अभियोजन साक्ष्य द्वारा उसकी संलिप्तता विधिवत सिद्ध हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि यदि मृतक चानन राम का इरादा आरोपी व्यक्तियों को चोट पहुंचाने का था, तो उसने लोगों के एक समूह के साथ झगड़ा करते समय जीप में 11 कारतूस नहीं छोड़े होते। अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा और निचली अदालतद्वारा पारित बरी करने के निर्णय को अपास्त

जा सकता है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम एस. खत्री का कहना है कि निचली अदालतने गलती से बरी करने का निर्णय नहीं सुनाया है और इस अपीलीय अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

हम चिकित्सा अधिकारी, डॉ.ओमप्रकाश मोदी की गवाही से शुरू करते हैं, जिनकी परीक्षण में पीडब्लू-5 के रूप में जांच की गई थी। उन्होंने घटना स्थल पर मृतक के शरीर की जांच की और उसके शरीर पर कुल बारह चोटें देखीं, जिनमें से चोट संख्या 1, 4, 9, 10, 11 और 12 एक कुंद हथियार के कारण हुई थीं और बाकी अधिकांश चोटें धारदार हथियार से लगी थीं। मृतक के गले पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। चोटों के कारण खून खून की कमी हो गई जिससे बेहोशी की स्थिति पैदा हो गई और मृतक की मृत्यु हो गई। मृतक के सिर व गर्दन पर चोट लगने से काफी खून बह गया था। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) तैयार की और उस पर हस्ताक्षर किए और सत्यापित किया कि यह सटीक है। उन्होंने आगे कहा कि चोट क्रमांक 7, जो कि गर्दन के दाहिनी ओर थोड़ा सा स्थित एक तेज हथियार के कारण 15x1.5 सेमी x 4 सेमी का घाव था, जिसने स्वरयंत्र और कैरोटिड वाहिका को दाहिनी ओर से काट दिया था, प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का पर्याप्त कारण था। चोट संख्या 2 और 3 तेज हथियार की चोटें थीं और जीवन के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकती थीं। चोट संख्या 2 15 x 1.5 सेमी हड्डी की गहरी चोट थी जो पश्चकपाल हड्डी के बाईं ओर से बाईं ओर स्थित मास्टॉयड प्रक्रिया के मध्य से होते हुए बाएं कान की लोब तक गई थी लेकिन मस्तिष्क को कोई चोट चोट नहीं पहुंची थी; ड्यूरा मेटर बरकरार था लेकिन ड्यूरा मेटर के बाहर खून जमा था। चोट संख्या 3 सिर की पिछली हड्डी के दाहिनी ओर 12 x 1.5 सेमी अर्ध-हड्डी-गहरा घाव था जिसने हड्डी को पूरी तरह से नहीं काटा था। डॉक्टर ने चोट संख्या 3 के संबंध में अदालत के समक्ष गवाही दी है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से घातक नहीं था, लेकिन अगर इलाज नहीं किया गया और खून की हानि हुई, तो यह घातक सिद्ध हो भी सकती है और नहीं भी। चोट संख्या 2 के लिए, उन्होंने कहा कि ड्यूरा मेटर पर रक्त जमा होने के कई

कारण हैं और यह भी संभव है कि चोट संख्या के साथ घायल होने पर भी कोई व्यक्ति दिनों तक जीवित रह सकता है। 2. उन्होंने आगे कहा कि यदि मृतक चोट संख्या 7 से घायल नहीं होता तो संभव था कि वह बच जाता। वह इस बात से सहमत नहीं है कि चूंकि उसके हृदय के सभी चार कक्ष खाली हो गए थे, इसलिए उसे लंबे समय तक खून बहता रहा रहा होगा; बल्कि, करीब पांच मिनट तक उसका खून बहता रहा होगा और उसकी मौत हो गई होगी। अंत में, पीडब्लू-5 ने कहा कि चोट संख्या 4 किसी कुंद सतह पर गिरने के कारण कारण हो सकती है और मृतक के शरीर पर कोई भी निशान नहीं पाए गए, जिसका अर्थ है कि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं पाए गए जिससे पता चल सके कि वह रस्सी से बंधा हुआ था। डॉक्टर के बयान की बारीकी से जांच करने से चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य के बीच विरोधाभास का पता चलता है और इस प्रकार, अभियोजन का मामला कमजोर हो जाता है।

इसके बाद, हम अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए चश्मदीद गवाहों की गवाही की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

मुकदमे में लीलाधर से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई। उनके अनुसार, बलदेव राम और चानन राम के बीच तब बहस हुई जब चानन राम उस दीवार के पास पहुंचा, जहां राजमिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाड़ा बलदेव राम और अन्य आरोपी व्यक्तियों का था और जिस जमीन पर बाड़ा बनाया गया था, उसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। पीडब्लू-1 के अनुसार, चानन राम ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ पकड़ रखी थी और सात आरोपी व्यक्ति, जो दीवार के दूसरी तरफ खड़े थे, बाहर आए और चानन राम को दीवार के दूसरी तरफ खींच लिया। उन्होंने चानन राम को घेर लिया और उसकी बंदूक छीन ली. लीलाधर का कहना है कि आरोपी शिवनारायण ने ही मृतक की बंदूक बंदूक छीन ली थी और बंदूक के लकड़ी के बट से उसके माथे पर वार किया था, जो टूट गया था। आरोपी छगन लाल काली रस्सी लेकर आया और सभी ने मिलकर मृतक के हाथ-हाथ-पैर बांध दिए। उसी भूखंड पर एक आउटहाउस है जहां वे चानन राम को ले गए, जबकि आरोपी बलदेव राम आउटहाउस के बाहर खड़ा था और अन्य आरोपियों को चानन राम को मारने के लिए चिल्लाया। पीडब्लू-1 लीलाधर द्वारा आगे कहा गया है कि आरोपी शिवनारायण एक फावड़ा ('कसिया') लाया और चानन राम की गर्दन के साथ-साथ उसके माथे के किनारे पर हमला किया; आरोपी अशोक कुदाल ('कस्सी') लाया और उसने भी चानन

चानन राम की गर्दन पर हमला कर दिया; आरोपी जीताराम ने चानन राम को लकड़ी के डंडे ('लाठी') से बार-बार पीटा। इस दौरान अन्य आरोपी चानन राम के पैर पकड़ रहे थे और बलदेवा राम बाहर खड़ा होकर दूसरों को चानन राम को मारने के लिए उकसा रहा था। पीडब्लू-1 के मुताबिक वहां और भी लोग जमा थे लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं पहचान पाया। उसने और राधाकिशन ने आरोपियों से कई बार चानन राम को नहीं मारने का का आग्रह किया था लेकिन उन्होंने नहीं सुनी; बल्कि उन्होंने दोनों को धमकी दी कि अगर वे वे पास आएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। चानन राम की पिटाई करने के बाद आरोपी लकड़ी का डंडा और फावड़ा अपने साथ लेकर भाग गए लेकिन बंदूक घटना स्थल पर ही छोड़ दी। चानन राम की हालत ठीक नहीं थी और उनके कपड़े खून से लथपथ थे। यह भी बताया गया कि जिस रस्सी से चानन राम को बांधा गया था वह रस्सी आउटहाउस में एक कोने में पड़ी हुई थी और जब तक वे अंदर गए, चानन राम की मृत्यु हो चुकी थी। बृजलाल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया जबकि लीलाधर और राधाकिशन राधाकिशन वहीं इंतजार करते रहे। 45 मिनिट बाद पुलिस डॉक्टर के साथ मौके पर पहुंची और जांच और सैंपल इकट्ठा करने में जुट गई। पीडब्लू-1 लीलाधर को आरोपी अशोक से लाठी की कथित बरामदगी का गवाह भी बनाया गया था (प्रदर्श पी-14)।

मुकदमे में आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जिरह के दौरान, पीडब्लू-1 लीलाधर ने स्वीकार किया कि वह चानन राम का चचेरा भाई था और चानन राम बलदेव राम को बेदखल करना चाहता था और सत्यनारायण और उसके बेटे पूनमचंद के पक्ष में उससे प्लॉट का कब्जा लेना चाहता था। चूँकि, चानन राम की बहन का विवाह पूनमचंद से हुआ था। इस प्रकार, पीडब्लू-1 एक इच्छुक गवाह था जिसकी गवाही की पुष्टि की जानी चाहिए और सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए; साथ ही, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके रिश्तेदार (मृतक) आरोपियों को बेदखल करना चाहते थे, जिसका मतलब है कि जब कथित घटना हुई तो आरोपियों का विवादित संपत्ति पर कब्जा था। विवादित भूखंड पर अभियुक्तों के कब्जे के संबंध में स्टार अभियोजन गवाह की स्वीकारोक्ति अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करती है और यह माना जा सकता है कि घटना की उत्पत्ति को दबा दिया गया है और अभियोजन ईमानदारी से शुरू नहीं किया गया है।

यह अजीब लगता है कि लीलाधर और राधाकिशन दोनों स्वाभाविक रूप से एक ही

समय में कथानक के अनुसार चल रहे थे जब घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो रही थी।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अगले चश्मदीद गवाह राधाकिशन से मुकदमे में पीडब्लू-4 के रूप में पूछताछ की गई और वह पीडब्लू-1 लीलाधर के साथ था जब उन दोनों ने घटना देखी थी। पीडब्लू-1 लीलाधर ने अदालत के सामने जो बयान दिया था, उसके अलावा, पीडब्लू-4 ने कहा कि आरोपी चानन राम को उस दीवार के ऊपर से प्लॉट पर ले गया, जिसका निर्माण किया जा रहा था और उसी के कारण कुछ ईंटें गिर गईं। उन्होंने कहा कि आरोपी शिव और श्याम सुंदर कुदाल लिए हुए थे और एक अन्य आरोपी, जिसे वह नहीं पहचान सके, लकड़ी का डंडा लिए हुए था। पीडब्लू-4 के अनुसार, आरोपी शिवनारायण ने चानन राम पर अपनी फावड़े से हमला किया था और उसकी गर्दन के साथ-साथ उसके माथे पर भी वार किया था; आरोपी श्याम सुंदर ने चानन राम के माथे के दूसरी तरफ वार किया था; और एक अन्य आरोपी, जिसका वह नाम नहीं बता सका, ने मृतक को लकड़ी के डंडे से मारा था। आगे कहा गया है कि वह, बृजलाल और लीलाधर आरोपियों से चानन राम को नहीं मारने का अनुरोध कर रहे थे; तब तक वहां और भी लोग जमा हो चुके थे, आरोपी भाग चुके थे और चानन राम की मौत हो चुकी थी। पीडब्लू-4 की गवाही में यह भी कहा गया है कि जब तीनों आरोपी चानन राम को पीट रहे थे, तो अन्य आरोपी चानन राम को पकड़ रहे थे और बलदेवा राम अन्य आरोपियों पर चानन राम को मारने के लिए चिल्ला रहा था। इसके अलावा, उस समय चानन राम के हाथ में एक बंदूक थी जिसे शिवनारायण ने सड़क पर छीन लिया था और आरोपी ने अपराध स्थल से भागते समय बंदूक को फेंक दिया था।

पीडब्लू-4 राधाकिशन ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि जब पुलिस वहां पहुंची तो तो बृजलाल घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। पुलिस रात करीब 12 बजे घटनास्थल पर पहुंची थी। और शाम तक वहीं मौजूद थे लेकिन बृजलाल तब तक नहीं आये थे। इस गवाह द्वारा की गई उपरोक्त स्वीकारोक्ति को बचाव पक्ष की दलील से बल मिलता है कि पहला मुखबिर बृजलाल अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था और अभियोजन का आधार झूठी रिपोर्ट की खोखली नींव पर आधारित है। मामले की उत्पत्ति संदेह के घेरे में है। रिकॉर्ड से कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि पहला सूचना देने वाला बृजलाल (पीडब्लू-9) घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और घटना के लंबे अंतराल के बाद पुलिस स्टेशन आया और

उसके आने तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने का इंतजार किया। एफ.आई.आर. अपराध स्थल स्थल पर पीडब्लू-9 बृजलाल की उपस्थिति ही संदिग्ध है और इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि शुरुआत से ही, अर्थात एफआईआर दर्ज करने से, सही तथ्य छुपाए गए थे और यही पहलू आगे अविश्वास पैदा करता है।

यह सुविधाजनक लगता है कि जब वे चानन राम को अंदर ले गए और उसकी पिटाई की, तो यह इस गवाह को दिखाई दे रहा था; यदि इतनी ही स्पष्ट दृश्यता थी तो वह यह क्यों नहीं देख सका कि आरोपी ने रस्सी खोली थी और वह कमरे के एक कोने में कैसे जमा हो गई। यह भी कहा गया है कि चानन राम का खून इतना बह चुका था कि शरीर के दोनों तरफ से 2-3 फुट तक खून बह चुका था, फिर भी रस्सी पर खून नहीं था। उपर्युक्त टिप्पणियों ने पीडब्लू-4 की गवाही पर संदेह की काली छाया डाल दी है।

मृतक के भाई बृजलाल से, जो घटना के दिन जीप में उसके साथ था, मुकदमे में अ.सा.-9 के रूप में परीक्षण किया गया। उनकी गवाही के अनुसार, उन्होंने आरोपियों से चानन राम को अकेला छोड़ने के लिए कहने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपियों द्वारा चानन राम को पीट-पीटकर मार डालने और चले जाने के बाद, पीडब्लू-9 बृजलाल ने पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीडब्लू-9 की गवाही में जो बातें केंद्र से बाहर हैं उनमें से एक यह है कि उसने कहा कि आरोपी ने चानन राम को घेर लिया था जिसने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी; हालाँकि आरोपी कथित तौर पर सात थे और इस प्रकार, संख्या में अधिक थे, फिर भी उन्हें यह डर कैसे नहीं था कि चानन राम अपने हाथों में पकड़े हथियार का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगा, अगर वे उसे चोट पहुँचाएँगे। पुलिस ने घटना स्थल से दो जीवित और उपयोग योग्य कारतूस बरामद किए, जिससे पता चलता है कि चानन राम के पास कारतूस लोड करने और गोली मारने के लिए तैयार थे या कम से कम वह बंदूक और कारतूस अपने हाथों में रखते हुए आरोपी को धमकी दे रहा था।

अपनी जिरह के दौरान, पीडब्लू-9 ने प्रकटन किया कि चानन राम और वह प्लॉट से से संबंधित विवाद के संबंध में पीडब्लू-3 सत्यनारायण की मदद करने के लिए अर्जुनसर आते आते थे। यह भी पता चला है कि वह लगभग सुबह 11.30 या 12.00 बजे के बीच अपनी

जीप से पुलिस स्टेशन गया था। और यह कि पुलिस लगभग एक घंटे तक घटना स्थल पर रुकी और दोपहर 03.00 बजे तक वहां से चली गयी. जो कि पीडब्लू-4 राधाकिशन ने अदालत के समक्ष जो बयान दिया था, उसके विरोधाभासी है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, गवाह पीडब्लू-9 बृजलाल की अपराध स्थल पर प्रासंगिक समय पर उपस्थिति ही संदिग्ध हो हो जाती है और साथ ही, बचाव पक्ष सच्चाई के करीब है।

पीडब्लू-9 ने अपनी जिरह में यह भी प्रकटन किया कि घटना स्थल पर पहले दौर की जांच के बाद पुलिस के वापस चले जाने के बाद उसने पुलिस स्टेशन में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब आरोपी उसे साजिश में ले जा रहे थे तो चानन राम ने उसे, लीलाधर और राधाकिशन को मदद के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने न तो उसे छुड़ाने में मदद करने के लिए कोई शारीरिक प्रयास किया और न ही आस-पास से किसी को बुलाया क्योंकि उन्हें उस समय कोई शव नहीं मिला। आरोपी शिवनारायण ने मृतक को बंदूक की बट से कई बार मारा था और उसकी कमर और पीठ पर चोट पहुंचाई थी। यह भी कहा गया है कि प्लॉट के पास सड़क पर 15-20 लोग खड़े थे और वे इस घटना को देख भी रहे थे।

यह किसी भी सामान्य विवेक वाले व्यक्ति के लिए अजीब और स्पष्ट नहीं है कि किसी के भाई को पीट-पीटकर मार डाला जा रहा है और आसपास के लोग मौजूद हैं, फिर भी, न तो वह आस-पास मौजूद लोगों से मदद मांगता है और न ही खुद हस्तक्षेप करके अपने भाई को बचाता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य मृतक की पीठ और कमर पर किसी कुंद वस्तु से चोट पहुंचाने के संबंध में इस गवाह के बयान की पुष्टि नहीं करते हैं। यह तथ्य बचाव पक्ष की इस दलील को और पुष्ट करता है कि यह गवाह अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था।

उपरोक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के अनुसार बताया गया है कि चानन राम को को आरोपियों ने रस्सी से बांध दिया था। अगर यह मान लिया जाए कि मृतक के हाथ-पैर काले टायर की रस्सी से बंधे थे जो बाद में प्लॉट पर बने कमरे के कोने में पड़ा मिला तो फिर छह में से तीन आरोपियों की जरूरत क्यों पड़ी? कथित तौर पर आरोपी को रोकने और और नियंत्रित करने के लिए कमरे के अंदर; और यदि मृतक इस हद तक विरोध कर रहा था था कि उसे रोकने के लिए तीन लोगों की आवश्यकता थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि

मृतक के शरीर पर उस पर हमले के दौरान उसके प्रतिरोध को दर्शाने के लिए कोई निशान नहीं थे। चिकित्सा साक्ष्य और पीडब्लू-5 डॉ.ओमप्रकाश मोदी की गवाही अभियोजन की कहानी के इस पहलू का समर्थन नहीं करती है; बल्कि, यह इसे खंडित करता है। अभियोजन अभियोजन पक्ष का यह स्वीकृत तथ्य है कि न तो रस्सी कहीं से कटी हुई थी और न ही रस्सी पर कोई खून के धब्बे थे। यदि आरोपी पर कई लोगों द्वारा इतनी बेरहमी से हमला किया जा रहा था तो रस्सी को भी आरोपी पर पड़ने वाले वार का खामियाजा भुगतना चाहिए चाहिए था, खासकर तेज धार वाले हथियारों से। पीडब्लू-4 राधाकिशन ने अपने शपथ बयान बयान में कहा है कि जब वह बृजलाल और लीलाधर के साथ कमरे के अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि चानन राम का बहुत खून बह चुका था; दरअसल, उन्होंने विस्तार से बताया बताया कि शरीर के दोनों तरफ दो-तीन फीट तक खून फैला हुआ था। यह अजीब है कि इस इस हद तक खून की हानि हुई लेकिन रस्सी को सही सलामत छोड़ दिया गया और फिर, चानन राम की पिटाई करने के बाद, आरोपियों ने रस्सी को हटाने और उसे कमरे के एक कोने में छुपाने में इतनी तेजी और कुशलता दिखाई कि वह घायल हो गया। काटा नहीं गया, खरोंचा नहीं गया या खून से लथपथ नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बंदूक का बट, जिससे यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने मृतक को मारा था, टूट गया था, लेकिन पीडब्लू-10 जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष अपनी जिरह में प्रकटन किया कि बंदूक क्षतिग्रस्त नहीं थी और साबुत थी। 12 बोर डबल बैरल बंदूक (प्रदर्श पी-6) के जब्ती ज्ञापन में बंदूक के कथित क्षतिग्रस्त हिस्से के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। पीडब्लू-9 बृजलाल के बयान से आरोपी शिवनारायण के खिलाफ बंदूक की बट से मृतक की कमर और पीठ पर 4-5 बार वार करने का आरोप सामने आया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) में पीठ पर किसी कुंद हथियार की चोट का प्रकटन नहीं हुआ है। और मृतक की गर्दन उपर्युक्त तथ्य अभियोजन पक्ष की कहानी की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है और चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने बंदूक के सही सलामत पाए जाने को लेकर झूठ बोला है।

घटना स्थल पर एकत्रित लोगों की संख्या तीन चश्मदीद गवाहों की गवाही में 50-60 से 15-20 तक भिन्न थी और यदि कुछ निश्चित संख्या में लोग घटना स्थल पर या

उसके आसपास मौजूद थे और घटना के गवाह थे। कुछ हद तक, तो उनमें से किसी को चश्मदीद गवाह क्यों नहीं बनाया गया या कोई भी हत्या की रिपोर्ट करने के लिए आगे क्यों क्यों नहीं आया कि उनके गांव में गवाह थे। पीडब्लू-4 राधाकिशन के जिरह के अवलोकन से से पता चला कि अर्जुनसर गांव में लगभग 200 घर हैं। यह वास्तव में अजीब लगता है कि कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए चश्मदीदों के अनुसार इतने सारे लोग वहां एकत्र हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसके बारे में तथ्य बताने के लिए आगे नहीं आया और यहां तक कि पीडब्लू-4 राधाकिशन भी वहां इकट्ठे हुए लोगों में से किसी को नहीं जानता था। तथ्य यह है कि यह एक छोटा सा गाँव है और ऐसे गाँवों में यह आम बात है कि अधिकांश लोग, यदि सभी नहीं, तो एक-दूसरे को जानते हैं।

मामले के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि भूखंड के ठीक पास एक पान की दुकान और एक पानी की दुकान (प्याऊ) थी, लेकिन फिर भी अभियोजन पक्ष इन दुकानदारों की गवाही को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है। इस प्रकार, स्वतंत्र गवाहों की उपलब्धता के बावजूद उन्हें प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन की कहानी की सत्यता पर और भी बुरा असर डालता है। हमें यह टिप्पणी करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर स्वतंत्र गवाहों को रोक दिया गया है और जो घटना घटी है उसके वास्तविक संस्करण को छिपाने का प्रयास किया गया है।

यह भी देखा गया है कि खून की हानि, घटना स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या, बंदूक के पिछले हिस्से से लगी चोटें आदि जैसे तथ्यों के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही में कई विसंगतियां हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन कथित चश्मदीदों ने अपने क्रॉस-क्वेश्चन में कहा है कि उन्होंने पुलिस को कुछ विवरण बताए थे, लेकिन पुलिस सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उनके बयानों में इसे दर्ज करने में विफल रही। इससे हमें विश्वास होता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू-1 लीलाधर, पीडब्लू-4 राधाकिशन और पीडब्लू-9 बृजलाल ने अदालत के सामने गवाही देते समय कहानियाँ बनाईं और सुनाईं और केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानी कहने की क्षमता के अनुसार ही सुना सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके शपथ पर दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर उल्लिखित विसंगतियाँ चश्मदीद गवाहों की गवाही में विसंगति दर्शाती हैं और उन्हें अविश्वसनीय बनाती हैं।

एक और बात जो हमें चकित करती है वह यह है कि मृतक का भाई, मृतक का चचेरा भाई और एक अन्य ज्ञात व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने मृतक को बचाने के लिए बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया। हंगामे के बाद वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए, ऐसे में अगर कथित चश्मदीदों ने अपना गुस्सा जाहिर किया होता या आसपास रहने वाले और कारोबार करने वाले लोगों से गुहार लगाई होती, तो शायद वे पीड़ित की मदद के लिए समय पर पहुंच पाते। यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने कभी भी हस्तक्षेप करने और आरोपियों को मृतक की हत्या करने से रोकने की कोशिश नहीं की और अपराध के दौरान वहां मौजूद रहने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं आई। पहले बताए गए अन्य तथ्यों के अलावा, ऊपर बताए गए तथ्य के आधार पर भी उनकी गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के संबंध में उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये गवाह वास्तव में घटना के समय वहां मौजूद थे और उन्होंने घटनाओं की श्रृंखला को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा था। इस मामले में दो आख्यान प्रस्तुत किए गए हैं और चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आख्यान पर उचित संदेह से परे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए अभियुक्तों द्वारा प्रदान किए गए विवरण और उनके बचाव पर विचार करने की आवश्यकता है।

यह बिल्कुल तय है कि मामले को सिद्ध करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और मामले को हर संदेह से परे सिद्ध करके इसे कम करना आवश्यक है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष के लिए समान स्तर के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बचाव में कोई दलील दी जाती है, तो यह पर्याप्त है कि उसे संभाव्यता की प्रबलता की सीमा तक सिद्ध किया जाए। मौजूदा मामले में बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई दलील सच्चाई के करीब लगती है। इस पहलू पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा चर्चा की गई है। ***सतीश कुमार बनाम राजस्थान सरकार*** ने 2005 में रिपोर्ट दी (2) डब्ल्यूएलसी 638 जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया:

> "86. इसलिए, जहां किसी तथ्य को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर पर है और जहां भार अभियुक्त पर है, वहां आवश्यक निश्चितता की डिग्री के बीच अंतर की एक सूक्ष्म लेकिन मौलिक रेखा है। जहां मुद्दे का बोझ

अभियोजन पर है, वहां इसे उचित संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। जहां वह एक आरोपी है, उसे उचित संदेह से परे इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है या डिफ़ॉल्ट रूप से "दोषी" का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि, भले ही वह निश्चित रूप से उन परिस्थितियों के अस्तित्व को सिद्ध करने में विफल रहता है, फिर भी वह आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों द्वारा शासित होने का दावा कर सकता है कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी सिद्ध न हो जाए। न्यायालय के मन में जो संदेह है, उसकी जानकारी उसे दी जानी चाहिए। यदि सभी साक्ष्यों की समीक्षा करने पर, न्यायालय को संदेह हो जाता है कि अभियुक्त के मामले को अपवाद के दायरे में लाने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं या नहीं, तो अभियुक्त बरी होने का पात्र है।

87. इस प्रकार, अपने मामले को उचित संदेह से परे सिद्ध करने का अभियोजन का सामान्य बोझ कभी नहीं बदलता है और यह हमेशा अभियोजन पक्ष पर रहता है।

उच्चतम न्यायालय ने ***मोहिंदर पाल जॉली बनाम पंजाब सरकार*** एआईआर 1979 एससी 577 में प्रकाशित में बताया कि अभियुक्त द्वारा उठाए गए निजी बचाव के अधिकार की दलील को संभाव्यता की सीमा तक बचाव करने की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण से निम्नलिखित अनुच्छेदों को उद्धृत करना प्रासंगिक समझा जाता है:

"संपत्ति या व्यक्ति की निजी रक्षा का अधिकार स्थापित करने का दायित्व अभियुक्त पर है, इसे संदेह से परे सिद्ध करने के मानक के आधार पर नहीं, बल्कि संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धांत के आधार पर, वह इस दलील को स्पष्ट रूप से ले भी सकता है और नहीं भी। या समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपनी याचिका में सफल हो सकता है यदि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर या साक्ष्य के अन्य टुकड़ों के आधार पर मामले के रिकॉर्ड में सामग्री लाने में सक्षम है। जाहिरा तौर पर उसने जो आपराधिक आपराधिक कृत्य किया, वह संपत्ति या व्यक्ति या दोनों की निजी सुरक्षा के

के उसके अधिकार के प्रयोग में उचित था। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग प्रयोग दंड संहिता की धारा 99 में प्रदान की गई सीमाओं और अपवादों के अधीन है।"

विचार करने योग्य एक और पहलू यह है कि कुछ स्वतंत्र गवाह जो घटनाओं के खुलासे और घटना की शुरुआत पर प्रकाश डाल सकते थे, उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दो विरोधाभासी आख्यानों के बीच भंवर सिंह नामक एक राजमिस्त्री और शेराराम नामक एक मजदूर कथित घटना की शुरुआत के समय साजिश पर मौजूद थे। इस प्रकार, घटना स्थल पर इन दो व्यक्तियों की उपस्थिति पर विवाद करने का कोई कारण नहीं है जब कथित लड़ाई शुरू हुई होगी और इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जा सकता था कि तथ्यों के वर्तमान सेट में कौन सी पक्षकार आक्रामक थी लेकिन बयान इनमें से दो व्यक्तियों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए जाने के बावजूद निचली अदालत के समक्ष दर्ज नहीं किए गए। यह अभियोजन पक्ष के मामले पर बुरा प्रभाव डालता है और अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालता है। इस प्रकार, यह न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी की वास्तविकता के संबंध में प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए राजी है। हमारी सुविचारित राय में, राजमिस्त्री और मजदूर को गवाह के रूप में प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है क्योंकि वे स्वतंत्र गवाह थे और इस संबंध में, निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के निर्णय में कोई विकृति नहीं दिखती है।

सत्यनारायण, जिन्होंने उस भूमि के स्वामित्व का दावा किया था जहां घटना हुई थी, से मुकदमे में पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई। उनके पास पंचायत द्वारा उनके और उनके बेटे के पक्ष में जारी किया गया एक पट्टा था (प्रदर्श पी-16 और पी-17)। उसकी गवाही से पता चलता है कि उसने चानन राम के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी ताकि वह उसकी ओर से कार्य कर सके। घटना के दिन, वह अपने खेत पर था और शाम को वापस अर्जुनसर आया जब उसे घटना के बारे में पता चला और तथ्य यह था कि बलदेव राम और उसके बेटों ने उसकी संपत्ति में घुसपैठ की थी और उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था।

जिरह करने पर, पीडब्लू-3 सत्यनारायण ने प्रकटन किया कि वह आरोपी बलदेव राम से विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करना चाहता था और आरोपी बलदेव राम और उसकी पत्नी मथुरा द्वारा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। उपरोक्त गवाह पीडब्लू-3 सत्यनारायण की गवाही से उभरने वाले तथ्यों से पता चलता है कि प्लॉट पर उसका कब्जा नहीं था और यह बचाव पक्ष के दावे को और मजबूत करता है कि आरोपी से जबरन प्लॉट पर कब्जा लेने के लिए, उक्त गवाह ने मृतक की सहायता ली।

अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से यह पता चलता है कि चानन राम एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को अपनी इच्छा की शर्तों पर सहमत होने के लिए मजबूर कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यनारायण आरोपी को बाहर निकालना चाहता था और किसी भी तरह से भूखंड पर कब्जा करना चाहता था और उसने मृतक को अपना मामला उठाने के लिए काम पर रखा था। रिकार्ड से पता चल रहा है कि मृतक एक गुस्सैल व्यक्तित्व और संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति था। 1980 तक उनके खिलाफ लगभग सात मामले दर्ज थे और अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के अनुसार, उनके आपराधिक इतिहास में लगभग बीस मामले शामिल हैं। यह संभव है कि मृतक एक प्रसिद्ध बाहुबली था जो लोगों को धमका सकता था या डरा सकता था और सत्यनारायण ने आरोपी पक्ष को बेदखल करने और भूखंड पर कब्जा पाने के लिए ऐसा करने के लिए उससे संपर्क किया था।

हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं है कि सत्यनारायण द्वारा मृतक के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन, आरोपी व्यक्तियों को धमकाकर या ऐसा भयानक माहौल बनाकर उन्हें वश में करने के लिए मृतक के साथ गैरविधिक अनुलग्नक करने या उसे काम पर रखने के बराबर है। ताकि आरोपी व्यक्तियों को अपनी जगह से कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। इस संबंध में हमारी टिप्पणियाँ अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से निकले तथ्य के आधार पर की गई हैं कि पीडब्लू-3 सत्यनारायण का भूखंड पर कब्जा नहीं था और वह किसी तरह कब्जा पाना चाहता था।

सत्यनारायण के शपथ पत्र से पता चला कि बृजलाल और मृतक चानन राम घटना स्थल से 70-80 किलोमीटर दूर रावतसर इलाके में रहते थे। अभियोजन पक्ष का यह रुख कि कि बृजलाल और चानन राम सहजरासर की यात्रा कर रहे थे और इंजन के अत्यधिक गर्म

होने के कारण उनका वाहन खराब हो गया था, एक बहाना प्रतीत होता है क्योंकि वे विवादित संपत्ति के ठीक पास रुके थे। इसके विपरीत, अधिक प्रशंसनीय तर्क यह है कि उनकी उनकी नकारात्मक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को देखते हुए, उन्हें आरोपी-प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने और साजिश के विवाद को निपटाने के स्पष्ट उद्देश्य से दूर से बुलाया गया था। अलावा, यह आकस्मिक नहीं हो सकता है कि चानन राम उसी समय प्लॉट पर पहुंचे जब आरोपी पक्ष द्वारा प्लॉट पर दीवार का निर्माण किया जा रहा था।

मुकदमे में पीडब्लू-10 के रूप में जांच अधिकारी से पूछताछ की गई और उसने बताया कि बृजलाल के पुलिस स्टेशन आने और कथित घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने अपराध स्थल का साइट प्लान तैयार किया, अपराध स्थल से बंदूक, कारतूस, मृतक के जूते आदि बरामद किए और 25.10.1988 को सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीडब्लू-10 ने अशोक (प्रदर्श पी-14), श्याम सुंदर (प्रदर्श पी-36) और शिवनारायण (प्रदर्श पी-38) की निशानदेही पर क्रमशः लाठी, कस्सी और कसिया की बरामदगी की। चूंकि, आरोपी श्याम सुंदर को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसके जूते और शर्ट पर खून पाया गया था, उसके जूते और शर्ट को भी पीडब्लू-10 राजपाल ने प्रदर्श पी-26 के तहत जब्त कर लिया था। मुकदमे में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा पूछताछ करने पर पीडब्लू-10 ने बताया कि बृजलाल पुलिस द्वारा व्यवस्थित निजी जीप में पुलिस के साथ घटना स्थल पर गया था। उन्होंने आगे कहा कि घटनास्थल से बरामद बंदूक टूटी हुई नहीं थी और जो रस्सी बरामद की गई थी वह न तो कहीं से कटी हुई थी और न ही उस पर कोई खून के धब्बे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने चानन राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 107 के तहत मामला दर्ज कराया है।

इस बात की प्रबल संभावना है कि एफआईआर (प्रदर्श पी-31) जांच के बाद का दस्तावेज है क्योंकि पीडब्लू-4 राधाकिशन ने अपने शपथ बयान में कहा है कि बृजलाल, जो अभियोजन के अनुसार पहला मुखबिर था, अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। पुलिस वहां पहुंची और शाम तक नजर नहीं आई जब पुलिस जांच करने के बाद चली गई जबकि जांच अधिकारी राजपाल (पीडब्लू-10) और बृजलाल के अनुसार, बृजलाल पुलिस के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां घटना हुई थी। अदालत के समक्ष बृजलाल की गवाही से यह भी पता चलता है कि जब वह पहले दौर की जांच के बाद पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन गया था, तो

तो उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, जबकि पीडब्लू-10 ने अदालत के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह वापस चला गया था। देर रात पुलिस स्टेशन जाना, उससे पहले नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में की गई जांच निष्पक्ष और पक्षपात रहित नहीं थी क्योंकि साइट योजनाओं में खामियां थीं; उदाहरण के लिए, यह नहीं दिखाया गया कि चश्मदीद गवाह कहाँ खड़े थे या दीवार कहाँ बनाई जा रही थी; और जिस दिन एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी दिन उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा गया था। यदि बृजलाल द्वारा घटना की सूचना दिए जाने पर दोपहर में ही एफआईआर पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे तो उसे उसी दिन मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं भेजा गया।

सीआरपीसी की धारा 157 के आदेश के अनुसार, रिपोर्ट "तुरंत" मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। संबंधित मजिस्ट्रेट को इसे भेजने में देरी से जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा होता है और अलंकरण और मनगढ़ंत कहानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ***छोटकऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** ने एआईआर 2022 एससी 4688 में बताया कि सीआरपीसी की धारा 157(1) के प्रावधान के अनुपालन और विशेष रूप से क्षेत्राधिकार अदालत में एफआईआर को प्रेषित करने में 5 दिनों की देरी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों का उल्लेख किया गया था। उस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसे घातक माना गया था। ***जफरूद्दीन और अन्य केरल राज्य*** ने एआईआर 2022 एससी 3627 में प्रकाशित, सीआरपीसी की धारा 157 के अनुसार मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में तत्परता के पहलू को दोहराया गया है और प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

> "26. जांच प्रक्रिया के दौरान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य जांच को न्यायसंगत और निष्पक्ष बनाना है। जांच अधिकारी को अपनी चल रही जांच में मजिस्ट्रेट को भी शामिल रखना होगा। इसका उद्देश्य संभावित बेईमानी से बचना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका होती है।
>
> 27. किसी आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक कानून कानून को क्रियान्वित करके जांच की प्रक्रिया शुरू करती है। मौखिक साक्ष्य

साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए यह निश्चित रूप से साक्ष्य का एक और मूल्यवान पहलू है। इसलिए, यह जरूरी है कि इस तरह की जानकारी जल्द से जल्द क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाए ताकि किसी भी संभावित एंटी-डेटिंग या एंटी-टाइमिंग से बचा जा सके, जिससे आरोपी को सच्चाई के विपरीत दोषी ठहराने वाली सामग्रियों को शामिल किया जा सके। सके। इस तरह की देरी से न केवल सहजता के लाभ से वंचित किया जा सकता है, बल्कि विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप रोचक संस्करण, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी प्रस्तुत करने से खतरा भी पैदा हो सकता है। हालाँकि, उचित जांच के बाद सामने आए अभियोजन अभियोजन पक्ष के मामले को अपास्त करने में केवल देरी ही एकमात्र कारक नहीं हो सकती है। अंततः, निर्णय लेना संबंधित न्यायालय को है। प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आशा है।

आइए, अब हम अभियुक्तों द्वारा उठाए गए निजी बचाव के अधिकार की दलील पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें क्योंकि इस न्यायालय की दृढ़ राय में, अभियोजन पक्ष कथित कथित अपराधों के कमीशन में अभियुक्तों की मिलीभगत स्थापित करने के पारंपरिक बोझ का का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार, अब, इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त ने निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया था या नहीं। रिकार्ड से पता चल रहा है कि मृतक कुख्यात व्यक्ति था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसा लगता है कि सत्यनारायण का मुकदमे की संपत्ति संपत्ति पर दावा था, लेकिन विवादित संपत्ति पर उसका कब्जा नहीं था और इसलिए, उसने आरोपी-प्रत्यर्थीगण से जबरदस्ती उक्त संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य से मृतक की सहायता ली। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आरोपी-प्रत्यर्थी अपराध स्थल पर मौजूद थे और एक राजमिस्त्री और एक मजदूर विवादित भूखंड पर दीवार का निर्माण कर रहे थे। उसी समय चानन राम घटनास्थल पर पहुंचा और उसके हाथ में बंदूक थी। संभवत: उसने अभियुक्तों को मुकदमे की संपत्ति से बेदखल करने के उद्देश्य से उन्हें डर में डालने की कोशिश की। उन्होंने राजमिस्त्री और मजदूर को मौका-ए-वारदात से भागने पर मजबूर कर

दिया। इसके बाद, उसने आरोपी-प्रत्यर्थीगण को बाहर निकालने की कोशिश की और उसी दौरान, उन्होंने हाथापाई की और उसे कुछ चोटें आईं जो उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध हुईं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 निजी रक्षा के अधिकार को नियंत्रित करने वाला कानून निर्धारित करती है। आईपीसी की धारा 96 में प्रावधान है कि कोई भी चीज़ अपराध के रूप में योग्य नहीं है अगर यह निजी सुरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। धारा 97 किसी व्यक्ति के शरीर के साथ-साथ संपत्ति के संबंध में निजी सुरक्षा के अधिकार के अर्थ को विस्तार से बताती है और यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना, चाहे वह चल या अचल संपत्ति हो, किसी ऐसे कार्य के खिलाफ जो अपराध बनता है जो चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है, या जो करने का प्रयास है चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार। यह अधिकार आईपीसी की धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के अधीन है। यह तीन कृत्यों को वर्गीकृत करता है जिनके लिए निजी रक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। वर्तमान मामले से संबंधित प्रतिबंध वह है जहां यह कहा गया है कि उन मामलों में निजी बचाव का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है जहां सार्वजनिक अधिकारियों की सुरक्षा का सहारा लेने का समय था। जैसाकि यहां ऊपर देखा गया है, अभियुक्तों के सामने कोई अवसर या विकल्प मौजूद नहीं था, जिसमें वे सार्वजनिक अधिकारियों से सुरक्षा मांग सकते थे या चानन राम का सामना किए बिना अपनी संपत्ति से बाहर जाने के लिए सुरक्षित पहुंच भी प्राप्त कर सकते थे। धारा 99 निजी रक्षा के अधिकार का दायरा भी प्रदान करती है और यह बताती है कि यह अधिकार किसी भी मामले में, रक्षा के उद्देश्य से जितना आवश्यक हो, उससे अधिक नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित नहीं है। चानन राम को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपियों का कृत्य, जिसके कारण मौत हुई, अपने बचाव के लिए आवश्यक था या नहीं, इसका विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ मामले को आईपीसी की धारा 100 के दायरे में लाती हैं। आईपीसी की धारा 100 को आसान संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत

किया गया है:

> **100. जब शरीर की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है–**शरीर की निजी रक्षा का अधिकार, अंतिम पूर्ववर्ती धारा में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत, स्वैच्छिक रूप से मृत्यु कारित करने या हमलावर को कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित होता है, यदि वह अपराध जो अधिकार के प्रयोग को बाधित करता है, आगे बताए गए किसी भी विवरण का हो, अर्थात्:**- पहला - ऐसा हमला जो उचित रूप से यह आशंका पैदा कर सकता है कि मृत्यु अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम होगी; दूसरा.–ऐसा हमला जिससे उचित रूप से यह आशंका पैदा हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम गंभीर चोट होगी;**
>
> तीसरा.– बलात्कार करने के इरादे से किया गया हमला;
>
> चौथा.– अप्राकृतिक वासना की तृप्ति के इरादे से किया गया हमला;
>
> पांचवां.– अपहरण या अगवा करने के इरादे से किया गया हमला;
>
> छठा.– गलत इरादे से किया गया हमला
>
> किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सीमित करना जो संभव हो उसे उचित रूप से यह आशंका दिलाएं कि वह अपनी रिहाई के लिए सार्वजनिक अधिकारियों का सहारा लेने में असमर्थ होगा।
>
> सातवां - एसिड फेंकने या पिलाने का कार्य या एसिड फेंकने या पिलाने का प्रयास जिससे उचित रूप से यह आशंका हो सकती है कि अन्यथा ऐसे कृत्य का परिणाम गंभीर चोट होगी।

धारा 100 में उल्लिखित हमले की पहली और दूसरी श्रेणियां, जो हमलावर की स्वेच्छा से मौत की सीमा तक निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करती हैं, वर्तमान मामले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। चूंकि, चानन राम बंदूक से लैस था और आरोपियों के पीछे भाग रहा था और उन्हें संपत्ति पर कब्ज़ा छोड़ने के लिए डराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यह उचित है कि आरोपियों को एहसास होगा कि वे गंभीर खतरे खतरे में हैं और यदि वे ऐसा करेंगे तो मौत होगी। मृतक के नाम और प्रतिष्ठा से जुड़ी बदनामी को देखते हुए हमला किया गया। इस तर्क के अनुसार, अभियुक्त द्वारा शरीर की

निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग दूसरी श्रेणी में भी आता है, जैसे कि मृत्यु नहीं, यह अभियुक्त की ओर से एक उचित विवेक था कि चानन राम उन्हें गंभीर चोट पहुँचा सकता है। है। जिस तरह से उसने हाथ में बंदूक और उपयोगी कारतूस लेकर उनका पीछा किया।

यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि आरोपी अशोक और जीताराम की कहानी के अनुसार, वे कमरे के अंदर गए, जबकि चानन राम गर्म था। उन्हें इस हद तक आशंका रही होगी कि वह अपनी कुख्याति और तथ्यों को देखते हुए उन पर अपने हथियार से हमला कर सकता है कि वह हाथ में बंदूक रखते हुए उसका पीछा कर रहा था और उन्हें विवादित संपत्ति छोड़ने की धमकी दे रहा था। वे कमरे में दाखिल हुए होंगे, कमरे में पड़े हुए औजार उठाए होंगे और प्रवेश द्वार के दोनों ओर खड़े हो गए होंगे ताकि चानन राम पर तुरंत हमला कर उसे रोक सकें। यही कारण है कि चानन राम को लगी चोटें धड़ से ऊपर हैं और मृतक के सिर, गर्दन और चेहरे के क्षेत्र को निशाना बना रही हैं।

मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मृतक चानन राम के खिलाफ राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। दिनांक 23.02.1987 के आदेश से पता चलता है कि हालांकि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने जारी नोटिस को अपास्त करना उचित समझा। कार्यवाही में उस समय अधिनियम के तहत चानन राम के खिलाफ, हालांकि, यह देखा गया कि 1980 तक, मृतक के खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज थे। किसी व्यक्ति का प्रतिशोध उसके मन में मौजूद डर की मात्रा पर निर्भर और आनुपातिक होता है। तथ्यों के वर्तमान सेट में, अभियुक्तों को यह ज्ञात था कि चानन राम कुख्यात था और उसका आपराधिक इतिहास था, इस प्रकार, उनके पास यह समझने का और भी कारण था कि जब चानन राम ने बंदूक लेकर उनका पीछा किया तो उनके जीवन को गंभीर खतरा था।

ऐसा लगता है कि संभावित, आसन्न खतरे को विफल करने की दृष्टि से, आरोपी-प्रत्यर्थीगण के पास एकमात्र विकल्प चानन राम को हथियारबंद करना था। चानन राम को निर्वस्त्र करने के दौरान, आरोपियों द्वारा उसे कुछ चोटें पहुंचाई गईं जो दुर्भाग्य से चानन राम के जीवन के लिए घातक सिद्ध हुईं। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि अभियुक्तों के पास विधिक कार्यवाही या सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता का सहारा लेने का पर्याप्त अवसर या पर्याप्त समय नहीं था क्योंकि वे एक चारदीवारी वाले इलाके में थे और चानन राम के साथ मुठभेड़ के बिना कोई रास्ता नहीं था। बंदूक से लैस, इस प्रकार, उनका

एकमात्र विकल्प खुद को बचाने के लिए मृतक को नुकसान पहुंचाना था क्योंकि वे क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते थे। यदि वे बिना किसी सीमा के बाहरी क्षेत्र में मौजूद होते, तो उनके लिए भागना या मदद के लिए पुकारना संभव होता, लेकिन एक बार जब वे कमरे में प्रवेश कर गए, तो भागने के अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए। चानन राम, जिसके हाथ में बंदूक थी, द्वारा पीछा किए जाने के दौरान कमरे में फंस जाने का अहसास और साथ ही आरोपी व्यक्तियों के मन में चानन राम के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में जो धारणा गई होगी, वह उनके लिए विनाशकारी रही होगी। ***बिश्ना एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल सरकार*** AIR 2006 SC 302 में प्रकाशित में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि जो लोग खतरे में हैं और मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका है, उनसे यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे अपने कार्यों के पक्ष और विपक्ष पर विचार करेंगे। या अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते समय शांतचित्त बने रहने में सक्षम हो सकें। ऊपर उल्लिखित उल्लिखित निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धरण है:

> "27. हालाँकि, बड़ी संख्या में मामलों में, इस न्यायालय ने यह कानून बनाया है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु या शारीरिक चोट की आशंका है, वह मौके पर और परिस्थितियों में, चोटों की संख्या को उन हमलावरों को निष्क्रिय करने के लिए जो हथियारों से लैस थे, गिनना संभव नहीं था। उत्तेजना और अशांत संतुलन के क्षणों में यह आशा करना अक्सर मुश्किल होता है कि पक्ष संयम बनाए रखेंगे और जवाबी कार्रवाई में केवल उतने ही बल का उपयोग करेंगे, जितना उसे होने वाले खतरे के अनुरूप हो, जहां बल के प्रयोग से हमला आसन्न हो। सभी परिस्थितियों को व्यावहारिकता के साथ देखने की आवश्यकता है और किसी भी अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो, यदि बचाव किया जाता है, तो आरोपी बरी होने का पात्र है और यदि नहीं, तो उसे हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में, उन्हें आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया जाएगा।

हमले के शिकार व्यक्ति से अंकगणितीय सटीकता की आशा नहीं की जा सकती और आत्म-संरक्षण एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है।

जिस प्रकार शरीर की निजी रक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु तक फैला हुआ है,

उसी प्रकार, संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार भी उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, गलती करने वाले को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु या किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है। धारा 99 में, जब कोई अपराध किया जाता है या ऐसा अपराध करने का प्रयास किया जाता है जो धारा 103 आईपीसी के तहत गिनाए गए अपराधों का हिस्सा है, तो अधिकार का प्रयोग होता है। यह अधिकार आईपीसी की धारा 103 के तहत निर्दिष्ट है और अपराध का विवरण जो संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार को गलत करने वाले की मौत तक विस्तारित विस्तारित करने की अनुमति दे सकता है और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के लिए जर्मन है, चौथी श्रेणी है जिसका संदर्भ के लिए नीचे उल्लेख किया गया है:

> "चौथा। - चोरी, शरारत, या **घर-अतिचार,** ऐसी परिस्थितियों में जो उचित रूप से यह आशंका पैदा कर सकती है कि परिणाम मृत्यु या गंभीर चोट होगी, यदि निजी रक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है।"

आईपीसी की धारा 102 शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और जारी रहने की बात करती है। यह प्रदान करता है कि उक्त अधिकार तब शुरू होता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध नहीं किया गया हो और यह तब तक जारी रहता है जब तक शरीर को खतरे की ऐसी आशंका होती है।

आरोपी अशोक और जीता राम का कहना है कि उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही चानन राम को मारा और वह जमीन पर गिर गया और उसी समय आरोपी जीता राम ने चानन राम के हाथ में रखी बंदूक और कारतूस उठाकर बाहर फेंक दिए ताकि वह उठकर उन पर दोबारा हमला न कर सके। जब चानन राम उस कमरे में दायर हुआ जहां आरोपी हाथ में बंदूक लेकर भागा और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा, तो इससे आरोपियों के मन में यह वाजिब आशंका पैदा हो गई होगी कि चानन राम उन्हें गोली मार सकता है और और इस प्रकार, उन्हें डर था कि उनके व्यक्तित्व को ख़तरा था। शरीर की निजी रक्षा का अधिकार तब लागू हुआ जब आशंका शुरू हुई और धारा 102 में यह आवश्यक नहीं है कि निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई अपराध किया जाना आवश्यक है; यह यह तब घटित होता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से कोई आशंका उत्पन्न होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मृतक पर तभी तक हमला किया जब तक कोई

आशंका थी और जैसे ही वह गिर गया, उन्होंने मृतक को मारना बंद कर दिया। ऐसा लगता लगता है कि आशंका की आसन्न और आकस्मिक प्रकृति के कारण, सब कुछ, कुछ ही मिनटों में हो गया होगा और मृतक को चोट पहुँचाने का कार्य कुछ ही सेकंड के भीतर हो गया होगा। उपरोक्त अवलोकन डॉ. मोदी (पीडब्लू-5) की चिकित्सकीय राय से समर्थित है, जिन्होंने कहा था कि मृतक को चोट लगने और मरने से पहले लगभग पांच मिनट तक खून खून बहता रहा होगा, जिससे पता चलता है कि घटना कुछ ही मिनटों में हुई होगी।

धारा 102 आईपीसी की धाराओं के समान, धारा 105 आईपीसी संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता को निर्दिष्ट करती है। संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति के लिए खतरे की उचित आशंका शुरू होती है और वर्तमान जैसे मामलों में जहां आपराधिक अतिचार होता है, यह तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार का कृत्य करता रहता है। चूंकि मृतक चानन राम ने कमरे तक आरोपियों का पीछा करना जारी रखा और भूखंड पर बने कमरे में प्रवेश किया, यह एक सुरक्षित अनुमान है कि उसने उनकी संपत्ति में अतिक्रमण किया और उनका पीछा करके और उस कमरे में प्रवेश करके अतिक्रमण जारी रखा, जहां से वे भाग निकले थे। आईपीसी की धारा 441 में यह प्रावधान है कि जो कोई किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में अपराध करने या ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने वाले या विधिपूर्वक प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करता है। संपत्ति, ऐसे किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से, या अपराध करने के इरादे से गैरविधिक रूप से वहां रखी जाती है, इसे "आपराधिक अतिचार" कहा जाता है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति में घातक हथियार लेकर घुसा था, जो आरोपियों के लिए उनकी संपत्ति के लिए खतरा और बेदखली के खतरे का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था।

अब, हम संबंधित संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के मुद्दे पर आते हैं। इस संबंध में, यह कहना पर्याप्त होगा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी भूखंड पर आरोपी व्यक्तियों के कब्जे और स्वामित्व को स्वीकार किया है, जिसकी चर्चा इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में की गई है। यह विधिक प्रावधान है कि स्वीकृत तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा धारा 58 के तहत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चूंकि रिकॉर्ड उपलब्ध है, हम

हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

आदेश दिनांक 24.05.1889 द्वारा, जिलाधीश ने ग्राम पंचायत, रामबाग द्वारा दिनांक 15.02.1988 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया था, जिसके द्वारा विवादित संपत्ति का पट्टा सत्यनारायण और पूनमचंद के पक्ष में जारी किया गया था, इस प्रकार, आरोपी विधिक रूप से घटना के समय स्वामित्व अधिकार वाली संपत्ति के कब्जे में थे। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत, रामबाग के कार्यालय के दस्तावेज़ (प्रदर्श डी-4) पर सरपंच मनीराम के हस्ताक्षर हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विवादित संपत्ति पर मथुरा पत्नी बलदेव राम का कब्ज़ा था और वहाँ उसी पर एक कमरा बना हुआ था। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से यह भी पता चलता है कि जिस भूखंड पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसका कब्ज़ा आरोपी बलदेव राम और उसके परिवार के पास था। यह सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है कि वास्तव में, आरोपी को बेदखल करने के लिए गवाह सत्यनारायण (पीडब्ल्यू -3) द्वारा मृतक को अनुलग्नक दिया गया था, इस प्रकार, प्रश्न में भूखंड पर आरोपी के कब्जे के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि हमलावर चानन राम ने विवादित भूखंड का कब्जा छोड़ने के लिए उन्हें डराने-धमकाने के इरादे से आरोपियों की संपत्ति, जो उनके सही कब्जे में थी, पर अतिक्रमण किया और आरोपियों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। उनके खिलाफ संपत्ति की निजी सुरक्षा और दी गई परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें उपलब्ध अधिकार से आगे नहीं बढ़ाया।

मो. रमज़ानी बनाम. दिल्ली राज्य AIR 1980 SC 1341 में प्रकाशित मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निजी सुरक्षा के अधिकार के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 पर चर्चा की और इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> “19. यह सामान्य बात है कि धारा 105, साक्ष्य अधिनियम के तहत एक एक आरोपी व्यक्ति पर निजी बचाव की अपनी दलील को स्थापित करने का दायित्व उतना कठिन नहीं है जितना कि अभियोजन पक्ष पर अपराध के हर घटक को स्थापित करने का बोझ है जो कि आरोपी है। उचित संदेह संदेह से परे, आरोप लगाया गया। यह और भी सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति को अपने या किसी अन्य के जीवन और अंग के आसन्न खतरे

का सामना करना पड़ता है, उससे खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक सटीक बल का आकलन करने तौलने की आशा नहीं की जाती है। इन सिद्धांतों के आलोक में देखा जाए, तो बचाव पक्ष, मौजूदा मामले में, संतुलन के साथ, संभावना के आधार पर यह स्थापित करने में सफल रहा रहा कि मृतक और अब्दुल रशीद ने क्रमशः सरिया और चाकू से लैस होकर, पहले मोहम्मद पर हमला किया। शफी और उसके बाद अपीलार्थी ने अपने पिता और खुद को और अधिक चोटों से बचाने के लिए मृतक पर पर हमला किया, भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि रिकॉर्ड पर पर मौजूद सामग्री धारा 105 के तहत अपीलार्थी की जिम्मेदारी की प्रकृति का निर्वहन करने में कम थी, साक्ष्य मोहम्मद की जांच करने वाले डॉक्टर के प्रस्तुत न होने पर कार्रवाई की गई। शफ़ी और अपीलार्थी, और मेडिको-लीगल रिपोर्ट तैयार की। पी.डब्लू., 15/ए और एक्स पी.डब्लू., पी.डब्लू., 15डीवाई, तो भी उस दक्षता और उससे उत्पन्न संदेह का लाभ अभियोजन को नहीं मिल सका। जैसाकि इसके मुख्य गवाह अब्दुल रशीद द्वारा प्रतिपादित अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पिता (मोहम्मद शफ़ी) और पुत्र (अपीलार्थी) दोनों ने वास्तव में मृतक पर हमले में भाग लिया था। उस कहानी का समर्थन करने के लिए, अभियोजन पक्ष 'मृतक के खून को मोहम्मद शफी के कपड़ों पर लगाने' की हद तक चला गया। मो. जानलेवा हमले के समय शफी द्वारा मृतक को पकड़ने की बात पाई गई और अभियोजन पक्ष की ओर से मोहम्मद की चोटों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। शफी और अपीलार्थी के बीच अंतिम विश्लेषण में एकमात्र विवेकपूर्ण कदम अदालत के लिए यह मानना था कि अभियोजन उचित संदेह से परे अपीलार्थी को दोषी ठहराने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है।"

वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए और मोहम्मद में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए ***मो. रमज़ानी*** (सुप्रा.), में इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि अभियुक्तों द्वारा ली गई निजी बचाव के अधिकार की दलील मामले का अधिक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण है और उनका मामला सिद्धांत के अनुसार आवश्यक निश्चितता की डिग्री

तक पर्याप्त रूप से सिद्ध हुआ है।

योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य, एआईआर 2016 एससी 5160 में प्रकाशित में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाले सुनहरे धागे में से एक यह है कि यदि किसी मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से दो दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, तो एक झुकाव अभियुक्त के अपराध के प्रति और दूसरा अभियुक्त की बेगुनाही की ओर झुकाव रखते हुए, वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के अनुकूल हो। 28 जुलाई, 2022 को हाल ही में आपराधिक अपील संख्या 2119/2010 में ***राजस्थान सरकार बनाम किस्तूरा राम*** शीर्षक से पारित निर्णय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप का दायरा तब तक सीमित है जब तक कि न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव या विकृत न हो। यह राय दी गई कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो बरी करने के आदेश को केवल इसलिए अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलीय न्यायालय का मानना है कि दोषसिद्धि अधिक संभावित है। बरी करने के आदेश में तभी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी जब निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव न हो।

उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और बार में दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को विद्वान निचली अदालतद्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। अभियोजन की कहानी उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं पाई गई और निजी बचाव के अधिकार के संबंध में अभियुक्त की दलील उचित और स्वीकार करने योग्य पाई गई।

हमारा मानना है कि आरोपी व्यक्तियों जीता राम और अशोक द्वारा बताई गई कहानी सच्चाई के करीब है; उन्होंने निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की और शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा बनाए गए माहौल में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था। यह भी सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि जब अप्रिय घटना घटी तो अन्य आरोपी अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे।

ऊपर की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के निर्णय को पलटने का कोई कारण नहीं है। हम विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा

गए निष्कर्ष से सहमत हैं और इस प्रकार इसकी पुष्टि करते हैं। अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार, अपील अपास्त की जाती है। सत्र प्रकरण संख्या 104/1988 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 11.12.1989 को दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय बरकरार रखा जाता है। अभियुक्तों के जमानत बांड उन्मोचित किये जाते हैं।

(फरजंद अली), न्यायमूर्ति **(विजय बिश्नोई), न्यायमूर्ति**

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।